1	2	3	4
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	14	421.43
14.	पंजाब नेशनल बैंक	292	1400.63
15.	पंजाब एंड सिंध बैंक	14	15.82
16.	सिंडिकेट बैंक	103	164.83
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	83	66.76
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	28	12.31
19.	यूको बैंक	58	73.17
20.	विजया बैंक	47	25.53
		2157	5348.02

टिप्पणी : यह जरूरी नहीं कि अंतर्ग्रस्त राशि के ऊपर दिए गए आंकड़े बैंकों को होने वाली वास्तविक हानि के द्योतक हों।

मध्य प्रदेश में अफीम की खेती के लिये भूमि का आबंटन

927. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में अफीम की खेती के लिए भूमि पट्टे पर दी जा रही है ;

(ख) वर्ष 1984-85 में उक्त जिलों में कितने हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी और क्या कुछ कृषकों को भूमि के कोई नये क्षेत्र भी पट्टे पर दिये गए थे ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चालू वर्ष में अफीम की खेती के क्षेत्र को कम कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि "चुम्बक कांड" में गवाही देने वाले अफीम उत्पादकों में से कई के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं ; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में पात्र कृषकों को अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं :-

(1) मंदसौर
(2) रतलाम
(3) उज्जैन
(4) शाजापुर
(5) राजगढ़
(6) झाबुआ

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उपर्युक्त जिलों में पोस्त खेती के लिए भूमि का क्षेत्र निम्नलिखित है :—

(हैक्टेयरों में)

क्रम सं०	जिला का नाम	क्षेत्र*
1.	मंदसौर	9,927
2.	रतलाम	1,705

(हैक्टेयरों में)

क्रम सं०	जिला का नाम	क्षेत्र*
3.	उज्जैन	75
4.	शाजापुर	92
5.	राजगढ़	16
6.	झाबुआ	18

(टिप्पणी : *उपर्युक्त दिए गए आंकड़ों को हेक्टेयर तक पूरा किया गया है।

तथापि किसी नये क्षेत्र में पोस्त की खेती नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 की सफल मौसम के दौरान 15 आरम्भ से अधिक व्यक्तिगत जोत के रकबे में 20 प्रतिशत की कटौती की गई जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में 35,713 काश्तकारों के संबंध में 651.69 हेक्टेयर की कुल कमी हुई है।

(ङ) वर्ष 1980-81 की तोलन कार्यवाही के दौरान मध्य प्रदेश में मारवा में "मैगनेट केस" से सम्बद्ध 63 काश्तकारों के लाइसेंस केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निष्कर्ष के आधार पर, वर्ष 1984-85 की फसल के दौरान रद्द कर दिए गए थे। इन काश्तकारों को वर्ष 1985-86 के दौरान भी लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

Regional Rural Banks

928. SHRI NIRMAL CHATTERJEE:
SHRI SHANTIMOY GHOSH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any problems concerning the Regional Rural Banks and their employees have been brought to Government's notice;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The main problems of Regional Rural Bank employees, brought to the notice of Government relate to parity of pay scales and other service conditions with commercial banks, inter-bank request transfers, setting up of a negotiating forum for discussing employees grievances, etc. The main problems being faced by Regional Rural Banks relate to industrial relations, attainment of viability, recruitment and manpower planning

(c) There is a Steering Committee headed by Chairman of NABARD to oversee the functioning of the Regional Rural Banks. A number of steps have been taken by Government to solve the problems of Regional Rural Banks and their employees. Separate State-level Forums under the convernorship of NABARD have been set up to discuss exclusively the problems and grievances of Regional Rural Bank staff. The recruitment of staff in Regional Rural Banks has been entrusted to Banking Service Recruitment Boards in order to streamline the process. With a view to suggesting suitable changes in the structure, planning and operational strategies of Regional Rural Banks, Government have set up a Working Group under the Chairmanship of Additional Secretary (Banking).

Production of sugar

929. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what was the number of sugar factories during the last three years, yearwise and Statewise;

(b) what was the production of sugar by these factories during the last three years, year-wise and how